



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2017/श्रावण 9, 1939

No. 303]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2017/SRAVANA 9, 1939

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2017

सं. भा.आ.प.—18(1)/2017—मेड./128371.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली, 2000” को पुनः संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन), 2017” कहा जाएगा।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” में शीर्षक “स्नातकोत्तर छात्रों का चयन” के अंतर्गत खंड 9(क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

खंड 9(2) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“डिप्लोमा और एम.डी./एम.एस. पाठ्यक्रमों के लिए मौजूदा योजना के अनुसार योगदान करने वाले राज्यों की 50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग हेतु नामजद प्राधिकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार होगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्र सरकार के आयुर्विज्ञान शिक्षण संस्थानों, संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों में सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा, एम.डी./एम.एस., डी.एम./एम.सीएच.) के लिए काउंसलिंग आयोजित करेगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय केंद्र सरकार के आयुर्विज्ञान शिक्षण संस्थानों, राज्य सरकार के आयुर्विज्ञान शिक्षण संस्थानों, मानित विश्वविद्यालयों, संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, राज्य/ संघ शासित क्षेत्र की विधान सभा द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, म्युनिसिपल निकायों, न्यास, सोसायटी, कंपनी या अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्थापित आयुर्विज्ञान शिक्षण संस्थानों में सभी अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों (डी.एम./एम.सीएच.) के लिए भी काउंसलिंग आयोजित करेगा।”

खंड 9क(3) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“राज्य सरकार द्वारा स्थापित सभी आयुर्विज्ञान शिक्षण संस्थानों सहित किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में सभी आयुर्विज्ञान शिक्षण संस्थानों, राज्य/संघ शासित क्षेत्र की विधान सभा के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, म्युनिसिपल निकाय, न्यास, सोसायटी, कंपनी या अल्पसंख्यक संस्थानों में डिप्लोमा और एम.डी./एम.एस. में दाखिले के लिए काउंसलिंग, राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी।”

अशोक कुमार हरित, उप-सचिव,

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामतः “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” दिनांक 07 अक्टूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग—III, खंड (4) असाधारण में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 03/03/2001, 06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006, 20/10/2008, 25/03/2009, 21/07/2009, 17/11/2009, 09/12/2009, 16/04/2010, 08/12/2010, 27/12/2010, 09/02/2012, 27/02/2012, 28/03/2012, 17/04/2013, 01/02/2016, 17/06/2016, 08/08/2016, 31/01/2017, 11/03/2017, 06/05/2017 और 27/06/2017 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2017

No. MCI-18(1)/2017-Med./128371.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000” namely:—

1. (i) These regulations may be called the “Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2017.”
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, in Clause 9A *under the* heading “Selection of postgraduate students”, the following shall be substituted:—

Clause 9A (2) shall be substituted as under:—

“The Designated Authority for counselling for the 50% All India Quota seats of the contributing States, as per the existing scheme for Diploma and M.D./M.S. courses shall be the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Further, the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India shall conduct counselling for all postgraduate courses [Diploma, M.D./M.S., D.M./M.Ch.] in Medical Educational Institutions of the Central Government, Universities established by an Act of Parliament and the Deemed Universities. Furthermore, the Directorate General of Health Services shall conduct the counselling for all Superspecialty courses (D.M./M.Ch.) in Medical Educational Institutions of the Central Government, Medical Educational Institutions of the State Government, Deemed Universities, Universities established by an Act of Parliament, Universities established by an Act of State/Union Territory Legislature, Medical Educational Institutions established by Municipal Bodies, Trust, Society, Company or Minority Institutions”.

Clause 9A (3), shall be substituted as under:—

“The counselling for admission to Diploma and M.D./M.S. in all Medical Educational Institutions in a State/Union Territory, including, Medical Educational Institutions established by the State Government, University established by an Act of State/Union Territory Legislature, Municipal Bodies Trust, Society, Company or *Minority Institutions shall be conducted by the State/Union Territory Government.*”

ASHOK KUMAR HARIT, Dy. Secy.

Footnote: The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 extraordinary of the Gazette of India on 7th October, 2000 and amended vide Medical Council of India Notification dated 03/03/2001, 06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006, 20/10/2008, 25/03/2009, 21/07/2009, 17/11/2009, 09/12/2009, 16/04/2010, 08/12/2010, 27/12/2010, 09/02/2012, 27/02/2012, 28/03/2012, 17/04/2013, 01/02/2016, 17/06/2016, 08/08/2016, 31/01/2017, 11/3/2017, 06/05/2017 and 27/06/2017.